

विचार बिन्दु

जो मनुष्य एक पाठशाला खोलता है वह एक जेलखाना बंद करता है। -अज्ञात

बदलता राजस्थान: शिक्षा का नया मॉडल

राजस्थान, अपनी सांस्कृतिक विरासत, रेगिस्तानी परंपराओं और विविध भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद, लगातार बदलते सामाजिक और आर्थिक परिदृश्यों के बीच अब शिक्षा के नए मॉडल की ओर अग्रसर है। परंपरागत रूप से यहाँ की शिक्षा ने लोकजीवन, हस्तशिल्प और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षण दिया है, परन्तु आज की आवश्यकता है कि वही विरासत आधुनिक शिक्षा के साथ मेल खाए ताकि युवा प्रतिभा वैश्विक प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ स्थानीय संवेदना और पहचान को भी बनाए रखे। राजस्थान में शिक्षा का नया मॉडल इसी संतुलन का परिणाम है: एक ऐसा मॉडल जो कौशल-प्रधान, क्षेत्रीय-संवेदनशील और तकनीक-सक्षम शिक्षा को प्राथमिकता देता है, साथ ही सामाजिक समावेशन और स्थायी विकास के लक्ष्यों को केन्द्र में रखता है।

नया मॉडल स्थानीयता और ग्लोबलाइजेशन के बीच पुल का काम करता है। इसके मूलभूत तत्वों में पाठ्यक्रम का संदर्भीकरण, व्यावहारिक कौशलों का समावेश, बहुभाषिक शिक्षा, तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का समुचित उपयोग शामिल है। राजस्थान की ग्रामीण तथा शहरी इकाइयों में भिन्न-भिन्न आवश्यकताएँ हैं, इसलिए मॉडल में अनुकूलन की गुंजाइश दी गई है ताकि प्रत्येक जिला, ब्लॉक और गाँव अपनी भौगोलिक, आर्थिक व सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण तैयार कर सकें। उदाहरण के लिए, ठेठ ग्रामीण क्षेत्र में जल-संवर्धन, वैकल्पिक कृषि तकनीक व स्थानीय हस्तशिल्प को पाठ्यचर्या में शामिल किया जा सकता है, जबकि शहरी केंद्रों में आईटी, डिजाइन और स्टार्टअप उद्यमिता पर जोर होगा। इस तरह शिक्षा युवाओं को न केवल नौकरी की तैयारी कराती है बल्कि उन्हें स्थानीय अर्थव्यवस्था में सकरात्मक योगदान देने योग्य भी बनाती है।

नए मॉडल का एक प्रमुख स्तंभ कौशल आधारित शिक्षा है। पारंपरिक शैक्षणिक परिणाम जैसे अंक और डिग्रियाँ आवश्यक तो हैं परन्तु आज रोजगार बाजार में सफलता का आधार तकनीकी, संचार एवं समाधान-उन्मुख कौशल हैं। राजस्थान सरकार और निजी संस्थाएँ मिलकर लैकेनल ट्रेनिंग, इंटरशिप और उद्योग-विद्यालय साझेदारियों को बढ़ावा दे रही हैं। स्कूलों में प्रारंभिक वर्ष से ही प्रोजेक्ट-आधारित लर्निंग तथा समकालीन कौशलों (डिजिटल साक्षरता, समस्या-समाधान, उद्यमशीलता) का समावेश किया गया है ताकि विद्यार्थी शीघ्रता से प्रयोगात्मक शिक्षा के माध्यम से कार्यक्षमता विकसित कर सकें। इससे नयी पीढ़ी को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार और सूक्ष्म उद्यम शुरू करने की प्रेरणा और प्रशिक्षण दोनों मिलते हैं।

शिक्षक-शक्ति का पुनरुद्धार नए मॉडल का अगला महत्वपूर्ण पक्ष है। राजस्थान में शिक्षकों को सिर्फ विषय-ज्ञान नहीं बल्कि मार्गदर्शन, व्यक्तित्व-निर्माण और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को दर्शाने वाले प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। शिक्षकों को सामुदायिक नेताओं के रूप में देखा जा रहा है वे बच्चों के साथ-साथ अभिवाचकों को भी शिक्षा के महत्व और नवीन पद्धतियों के प्रति संवेदित करते हैं। यह बदलाव शिक्षण को केवल कक्षाकक्षीय गतिविधि से निकालकर एक समुदाय-समावेशी अभियान बनाता है, जहाँ शिक्षक स्थानीय सांस्कृतिक विद्याओं, पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक कौशलों के मध्य संपर्क स्थापित करें।

तकनीकी शिक्षा संस्थान जब कला, साहित्य व संगीत जैसे क्षेत्रों पर काम करते हैं तो यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि हमारी पुरातन परंपराओं का आदर करने वाली एक नई पीढ़ी सशक्त हो रही है। आधुनिक तकनीकी ज्ञान और शिल्पीय कौशल के साथ सांस्कृतिक एवं कलात्मक संवेदनशीलता जोड़ने की यह दिशा नई शिक्षा नीति के मूल सिद्धांतों से मेल खाती है, जो बहुआयामी शिक्षा, क्रॉसडिडिप्लिनरी लर्निंग और स्थानीय ज्ञान के संरक्षण पर जोर देती है। महेश स्वामी जैसे विचारक और मार्गदर्शक, जिनकी सोच में परंपरा और नवाचार का संयोजन है, उन युवा मनों में जिजीविषा जगाते हैं जो तकनीक को सिर्फ उपकरण के रूप में नहीं, बल्कि सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में देखते हैं। जब संस्थान तकनीकी पाठ्यक्रमों में संगीत, लोककथाएँ, लोकहस्तकला और साहित्य को शामिल करते हैं, तो विद्यार्थी तकनीकी समस्याओं के समाधान में मानवीय और संवेदनशील दृष्टिकोण लाते हैं, स्थानीय समृद्ध संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान को नई विधियों से पुनर्जीवित करते हैं, और रोजगार व उद्यमशीलता के नये रास्ते खोलते हैं। नई शिक्षा नीति की भाषा में यह समावेशिता आत्मसात करना न केवल रचनात्मकता व आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है, बल्कि सांस्कृतिक आत्मसत्ता को भी मजबूत बनाता है यानी तकनीकी प्रति और सांस्कृतिक जड़ों के बीच एक जीवंत सेतु निर्मित होता है। ऐसे प्रयास न केवल विद्यार्थियों को बहुआयामी कौशल देते हैं, बल्कि समाज को भी एक ऐसी दिशा प्रदान करते हैं जहाँ आधुनिकता और परंपरा

राजस्थान का नया शिक्षा मॉडल एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो वैश्विक मानकों के साथ स्थानीय संवेदनशीलता का संयोजन करता है। यह मॉडल कौशल आधारित, बहुभाषिक, तकनीक समर्थित और सांस्कृतिक रूप से समावेशी है। यदि इसे सजीव रूप में लागू किया जाए अर्थात् नीतिगत समर्थन, समुदायिक भागीदारी और सतत निवेश के साथ तो यह न केवल शैक्षिक सुधार लाएगा बल्कि सामाजिक और आर्थिक पुनरुत्थान का भी मार्ग प्रशस्त करेगा।

सहअस्तित्व में, नवोन्मेष को मानवीय अर्थ और स्थानीय प्रसंगिकता प्रदान करें।

शिक्षा और स्थानीय अर्थव्यवस्था के बीच संबंध को मजबूती देने के लिए कैरियर मार्गदर्शन और स्थानीय-रोजगार मानचित्र बनाये गए हैं। युवा अब शहरों की ओर केवल नौकरियों की तलाश में नहीं भाग रहे; उन्हें स्थानीय पारंपरिक उद्योग, पर्यटन, और हरित अर्थव्यवस्था (जैसे जल प्रबंधन, अक्षय ऊर्जा) में अवसर दिखाये जा रहे हैं। स्कूलों और स्थानीय उद्योगों के बीच समन्वय से इंटरशिप और छोटे व्यवसाय आरम्भ करने वाले प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं। इससे ग्रामीण पलायन पर नियंत्रण रहता है और स्थानीय समुदायों की आर्थिक स्वायत्तता बढ़ती है।

पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक संरक्षण का समावेश भी इस मॉडल की विशिष्टता है। राजस्थान की लोककथाएँ, लोकसंगीत, हस्तशिल्प और पर्यावरणीय जीवन-ज्ञान को सीखने के माध्यम बनाया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों को अपनी जड़ें जानने का अवसर मिलता है और सांस्कृतिक पर्यटन तथा हस्तशिल्प कारोबार में रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। शिक्षा अब केवल आधुनिक विज्ञान तक सीमित नहीं है; यह एक ऐसा माध्यम है जो स्थानीय पहचान को सम्मान देते हुए नवाचार को प्रोत्साहित करता है।

नवोन्मेष और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूलों तथा कॉलेजों में सक्रिय प्रयोगशालाओं और इन्वेंशन हब का निर्माण हो रहा है। छोटे स्तर पर स्टूडेंट-प्रोजेक्ट फंडिंग, मेकथॉन और स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु प्रतियोगिताएँ आयोजित की जा रही हैं। इससे छात्रों में समस्या-समाधान की प्रवृत्ति, टीम-वर्क और वास्तविक दुनिया की नौकरी योग्य क्षमताएँ विकसित होती हैं। इसके साथ ही, उच्च शिक्षा संस्थानों में रिसर्च को स्थानीय मुद्दों जैसे जल संकट, सूखा-प्रबंधन और पारंपरिक जल संरचनाओं की आधुनिक व्याख्या पर केंद्रित किया जा रहा है।

वित्तीय और नीतिगत समर्थन का भी विशेष प्रावधान इस मॉडल में है। शिक्षा के नवाचारों के लिए अनुदान, निजी-सरकारी भागीदारी और सीएसआर फंड का उपयोग कर विशेष परियोजनाएँ चालू की जा रही हैं। यह मॉडल के स्थानीय आवश्यकताओं और तकनीकी प्रगति के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। सफलता का आकलन अब केवल परीक्षाफल से नहीं बल्कि व्यावसायिक सफलता, सामुदायिक परिवर्तन तथा पर्यावरणीय संकेतकों के आधार पर भी किया जाता है।

हालाँकि चुनौतियाँ अभी भी कम नहीं हैं। शिक्षकों की कमी, दूरदराज इलाकों में बुनियादी ढांचे की कमी, तथा सामाजिक मान्यताएँ जो कुछ समुदायों में लड़कियों को पढ़ाई पर प्रभाव डालती हैं-ये बाधाएँ बनी हुई हैं। इन चुनौतियों का समाधान केवल शिक्षा नीति से नहीं बल्कि समग्र सामाजिक परिवर्तन, सामुदायिक जागरूकता और दीर्घकालिक निवेश से किया जा सकता है। इसी कारण शिक्षा के नए मॉडल में सरकार, स्थानीय समुदाय, गैर-सरकारी संस्थाएँ और निजी क्षेत्र-सभी भागीदारों की सक्रिय सहभागिता अनिवार्य मानी गई है।

राजस्थान का नया शिक्षा मॉडल एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो वैश्विक मानकों के साथ स्थानीय संवेदनशीलता का संयोजन करता है। यह मॉडल कौशल आधारित, बहुभाषिक, तकनीक समर्थित और सांस्कृतिक रूप से समावेशी है। यदि इसे सजीव रूप में लागू किया जाए अर्थात् नीतिगत समर्थन, समुदायिक भागीदारी और सतत निवेश के साथ तो यह न केवल शैक्षिक सुधार लाएगा बल्कि सामाजिक और आर्थिक पुनरुत्थान का भी मार्ग प्रशस्त करेगा। राजस्थान की युवा पीढ़ी, जो अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी और वैश्विक क्षितियों के लिए तैयार होगी, निश्चय ही राज्य को एक नया, सशक्त और आत्मनिर्भर भविष्य दे सकती है।

-अतिथि संपादक,
अविनाश जोशी,
वरिष्ठ पत्रकार एवं कॉर्पोरेट सलाहकार



राजेन्द्र भाणावत

मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए 3 मई, 2026 को आयोजित नीट परीक्षा, पेपर लोक होने के कारण निरस्त कर दी गई थी। अब यह पुनः 21 जून 2026 को आयोजित होने जा रही है। इस परीक्षा की तैयारी के समाचार, जिस प्रकार से मीडिया में आ रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि यह परीक्षा नहीं अपितु युद्ध की तैयारी हो रही है।

यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय 21 जून को होने वाले नीट की मॉनिटरिंग अपने स्तर पर कर रहा है, जबकि इसे आयोजित करने की पूरी जिम्मेदारी एन टी ए की है। एन टी ए का तो गठन ही इस प्रकार की परीक्षाओं के आयोजन के लिए 2019 में किया गया था। क्या एक परीक्षा की मॉनिटरिंग के अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय के पास और कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है? पूरे देश में संचार के प्रमुख साधन 'टेलीग्राम' पर 22 जून तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। नीट के प्रश्न पत्रों को विभिन्न केंद्रों तक पहुंचाने के लिए वायु सेना के वायुयानों और हेलीकॉप्टरों द्वारा 200 से अधिक उड़ानें भरी गई हैं। इन पर कितना खर्चा हुआ होगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस तरह की तैयारी तो स्वतंत्रता के बाद, शायद किसी भी परीक्षा के लिए नहीं की गई।

प्रश्न पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वायु सेना के विमान और हेलीकॉप्टरों का प्रयोग हास्यास्पद है। क्या जाँच में कहीं पर यह

यह परीक्षा है या युद्ध ?

सिद्ध हुआ है कि पेपर, परिवहन के दौरान लोक हुए थे? पेपर लोक की घटना को रोकने के बारे में आवश्यक प्रभावी कार्यवाही तभी संभव है जब यह पता किया जा सके कि पेपर लोक किसके स्तर पर हुआ? मजे की बात तो यह है कि एन टी ए तो पेपर लोक होना ही नहीं मान रहा है। फिर क्यों पहली परीक्षा निरस्त करके दोबारा कराई जा रही है? क्या यह 22 लाख छात्रों के साथ मजाक नहीं है? नीट के पेपर, 2024 में भी लोक हुए थे और कई व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी। आज वे सभी जमानत पर हैं और शायद पुनः उसी काम में लग गए होंगे। इसी प्रकार 2025 के नीट पेपर भी लोक हुए थे लेकिन उसके ज़्यादा समाचार नहीं आए। बाद में पता लगा कि कुछ व्यक्तियों को पेपर मिले थे और उसके आधार पर, अयोग्य होते हुए भी उनका चयन हो गया था। आज वे सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं।

पेपर लोक की घटनाएं बार-बार होने का प्रमुख कारण ही यह है कि इसके कारणों का सही पता नहीं लगाया जाता। इसी कारण, इसे रोकने के लिए कोई कार्रवाई भी नहीं हो पाती है। पेपर लोक गंभीर अपराध है और उसके साथ विद्यार्थियों का भविष्य जुड़ा है फिर भी इसमें लिप्त लोगों पर कठोर कार्यवाही न होना सरकारी संवेदनहीनता का ही द्योतक है। एक व्यक्ति की हत्या के लिए हत्यारे को आजीवन कारावास या फांसी की सजा होती है। नीट के पेपर लोक के कारण हुई लगभग 20 विद्यार्थियों की आत्महत्या की जिम्मेदारी एन टी ए के अधिकारियों की क्यों नहीं मानी जानी चाहिए? सरकार द्वारा ऐसा कुछ करना तो पूरे, उसके शिक्षा मंत्रों तक को अब तक पद से नहीं हटाया गया है, जबकि इस बारे में आंदोलन लगातार चल रहा है।

केंद्र सरकार, परीक्षा आयोग को भी एक इवेंट बना रही है। 'टेलीग्राम' बंद करना, वायु सेना के माध्यम से पेपर पहुंचाना और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा मॉनिटरिंग तथा इसे मीडिया में प्रमुखता से प्रचारित, प्रसारित करना इवेंट आयोजन जैसा ही तो है। समाचार पत्रों के मुखपृष्ठ पर वायुसेना के विमानों द्वारा प्रश्न पत्र ले जाने के फोटो प्रकाशित करना भी इसी का हिस्सा है।

नीट जैसी परीक्षा के पेपर कई व्यक्तिक मिलकर तैयार करते हैं किंतु अंतिम प्रश्न पत्र में कौन से प्रश्न होंगे, इसकी जानकारी एन टी ए के ही कुछ अधिकारियों को होती है। एनटीए के अध्यक्ष अभी तक वही बने हुए हैं और पूर्व महानिदेशक को प्रमोशन देकर कहीं और लगा दिया गया है। इसे जवाबदेही का पूर्णतया अभाव ही कहा जाएगा। वायुसेना के माध्यम से पेपर भेजने का निर्णय कुछ कुछ वैसा ही है, जैसे पेपर लोक के लिए। वायुसेना के विमानों को पाइपलाइन में लीक हो किंतु बिना यह पता लगाए कि लीकज कहां पर है, उसे ठीक करने का प्रयास किया जाता। गाड़ी के पहिए का पंचर होने पर, पहले ठीक करने वाला पानी डालकर यह देखाता है कि कहां से पानी का बुलबुला निकल रहे हैं ताकि वह पता लगा सके कि पंचर कहां हुआ है? और फिर, वह उसे मरम्मत करने का कार्य करता है। इतनी साधारण सी बात भी सरकारी, नीट की परीक्षा के लिए समझ पा रही है। ऐसा लगता है वह केवल अंधेरे में तीर चला रही है और इसे भी अपने प्रचार का माध्यम बना रही है।

देश में प्रतिबंध विभिन्न हज़ारों परीक्षाओं के लाखों प्रश्न पत्र होते हैं जिनमें करोड़ों विद्यार्थी बैठते हैं। इस प्रकार से वायु सेना का उपयोग यदि प्रश्न पत्र ले जाने के लिए किया गया तो कितनी परीक्षाओं में ऐसा किया जा सकेगा? छात्र के लिए प्रत्येक परीक्षा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उपयुक्त विश्वसनीय व्यक्तियों को परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं में लगाया जाए। उनकी ईमानदारी पर किसी प्रकार का संदेह न हो। विमानों द्वारा प्रश्न पत्र ले जाना किसी पेड़ के पत्तों को तोड़ने जैसा है जिसका कोई लाभ नहीं है। समस्याएँ हल करने के लिए समस्या की जड़ पर प्रहार करना आवश्यक है।

क्या भारत भविष्य के 'वाटर इमरजेंसी' की ओर बढ़ रहा है?



राम शर्मा

जल जीवन का आधार है। मानव सभ्यता का विकास नदियों के किनारे हुआ और आज भी किसी देश की समृद्धि का एक महत्वपूर्ण आधार उसके जल संसाधन है। लेकिन 21 वीं सदी में दुनिया जिस सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, उनमें जल संकट प्रमुख है। भारत भी इस चुनौती से अछूता नहीं है। देश की बढ़ती आबादी, अनियोजित शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन और भूजल के अंधाधुंध दोहन ने जल संकट को गंभीर बना दिया है। आज यह प्रश्न प्रासंगिक हो गया है कि क्या भारत भविष्य में किसी 'वाटर इमरजेंसी' की ओर बढ़ रहा है?

भारत विश्व की लगभग 18 प्रतिशत आबादी का घर है, जबकि उसके पास विश्व के केवल 4 प्रतिशत नीचे जल संसाधन है। यह असंतुलन भीटे आप में एक बड़ी चुनौती है। पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकरण के कारण जल की मांग

लगातार बढ़ी है, लेकिन जल संसाधनों का विस्तार उसी अनुपात में नहीं हो पाया। परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता तेजी से घट रही है। देश के अनेक शहर पहले ही जल संकट की गंभीर स्थिति का सामना कर चुके हैं। कुछ वर्षों पहले दक्षिण भारत के प्रमुख महानगरों में से एक, बंगलुरु को भीषण जल संकट का सामना करना पड़ा था। कई इलाकों में टैंकरों के सहारे पानी की आपूर्ति करनी पड़ी। इसी प्रकार चेन्नई, दिल्ली और अन्य महानगरों में भी समय-समय पर जल संकट की स्थिति उत्पन्न होती रही है। यह संकेत है कि समस्या अब केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित नहीं रही, बल्कि शहरी भारत भी इसकी चपेट में आ रहा है। जल संकट के पीछे सबसे बड़ा कारण भूजल का अत्यधिक दोहन है। भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपभोक्ता माना जाता है। कृषि, श्रमोत्पन्न और उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लाखों टचयूनिट और बोरेवेल लगातार चयन से पानी निकाल रहे हैं। कई राज्यों में भूजल स्तर खतरनाक रूप से नीचे जा चुका है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में भूजल का स्तर वर्ष दर वर्ष गिरता जा रहा है। यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले वर्षों में पेयजल की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बन सकती है।

जलवायु परिवर्तन ने इस संकट को और जटिल बना दिया है। पहले जहां मानसून अपेक्षाकृत नियमित रहता था, वहीं अब वर्षा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। कहीं अत्यधिक वर्षा हो रही है तो कहीं लंबे समय तक सूखे जैसी स्थिति बनी रहती है। कई क्षेत्रों में कुछ दिनों की भारी बारिश पूरे वर्ष की औसत वर्षा को पूरा कर देती है, लेकिन उसका अधिकांश जल बहकर समुद्र में चला जाता है। इससे भूजल पुनर्भरण की प्रक्रिया प्रभावित होती है और जल संकट गहराता है। भारत में जल प्रबंधन की कमजोर व्यवस्था भी चिंता का विषय है। आज भी वर्षा जल का बड़ा हिस्सा संरक्षित नहीं किया जाता। जल संरक्षण की योजनाएँ कई बार कागज़ों तक सीमित रह जाती हैं। शहरों में तालाब, झीलें और पारंपरिक जल स्रोत लगातार समाप्त होते जा रहे हैं। जिन जलाशयों ने सदियों तक समाज की जल आवश्यकताओं को पूरा किया, वे अतिक्रमण और उपेक्षा का शिकार हो गए हैं। कृषि क्षेत्र में भी जल का उपयोग अत्यधिक और कई बार अनियोजित तरीके से होता है। भारत में उपलब्ध मीठे जल का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा कृषि में उपयोग किया जाता है। अनेक क्षेत्रों में ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जिनमें अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में धान और गेहूँ जैसी फसलों की खेती भूजल पर भारी दबाव डालती है। यदि कृषि पद्धतियों में सुधार नहीं किया गया तो भविष्य में जल संकट और गंभीर हो सकता है।

शहरीकरण भी जल संकट को बढ़ा रहा है। तेजी से फैलते शहरों में कंक्रीट का विस्तार हो रहा है, जिससे वर्षा जल जमीन में समाहित नहीं हो पाता। इसके अलावा पाइपलाइन लीकज और खराब वितरण प्रणाली के कारण बड़ी मात्रा में पानी बर्बाद हो

जाता है। कई शहरों में प्रतिदिन लाखों लीटर पानी रिसाव के कारण नष्ट हो जाता है। यह स्थिति तब और चिंताजनक हो जाती है जब लाखों लोगों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता। जल संकट का सीधा प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। कृषि उत्पादन में कमी, उद्योगों की उत्पादन क्षमता पर असर और ऊर्जा क्षेत्र में चुनौतियाँ आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकती हैं। जल की कमी से खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है, जिससे महंगाई बढ़ने की संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त पानी को लेकर सामाजिक तनाव और क्षेत्रीय विवाद भी बढ़ सकते हैं।

हाल के वर्षों में वैश्विक स्तर पर बढ़ते तापमान और चरम मौसमीय घटनाओं ने जल संकट को और गंभीर बना दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दशकों में जल की उपलब्धता भारत के विकास के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक बन सकती है। यह स्थिति केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक संकट का रूप भी ले सकती है। हालाँकि स्थिति पूरी तरह निराशाजनक नहीं है। भारत के पास इस चुनौती से निपटने के पर्याप्त अवसर भी हैं। सबसे पहले जल संरक्षण को जल आंदोलन का रूप देना होगा। वर्षा जल संचयन को प्रत्येक घर, विद्यालय, उद्योग और सरकारी भवन में अनिवार्य बनाने की दिशा में गंभीर प्रयास आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों, बावड़ियों और पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन पर

सर्वजनिक रूप से सरकार को यह बताना चाहिए कि 2024 में प्रश्न पत्र लोक करने के लिए जिम्मेदार कौन थे और उन्हें अब तक सजा क्यों नहीं हुई? इसी प्रकार नीट 2026 के लिए यह बताना आवश्यक है कि किस स्तर पर पेपर लोक हुए? एन टी ए अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री के अपने पद पर बने रहते हुए इसकी कोई निष्पक्ष जांच हो पाएगी, यह संभव नहीं है। टेलीग्राम जैसे प्रमुख संचार माध्यम को प्रतिबंधित करना युद्ध के समय उठाए गए कदम जैसा है। इस कारण लाखों लोगों को प्रेशान होना पड़ रहा है। सरकार जब भी इंटरनेट की सेवा प्रतिबंधित करती है तो पूरे क्षेत्र में किस प्रकार सामान्य गतिविधियाँ ठप हो जाती हैं, इसका अंदाजा नागरिकों को है। केवल परीक्षा आयोजन के लिए टेलीग्राम जैसे महत्वपूर्ण साधन को प्रतिबंधित करना नितांत अनुचित है। सरकार को शायद इस बात का भी पता है कि आज के युवा पेपर लोक के कई वैकल्पिक तरीके अपना सकते हैं। तो फिर, इस प्रतिबंध का कोई अर्थ भी नहीं रह जाता। जैसे मोबाइल इंटरनेट को बंद करने पर, वाई-फाई तो चालू रहता ही है। मोबाइल इंटरनेट को बंद करने से परेशानी होती है किंतु इसका कोई विशेष लाभ प्रतिबंध लगाने वालों को नहीं होता है। टेलीग्राम कंपनी, प्रतिबंध के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में गई अवश्य है किंतु अब तक उसे कोई राहत नहीं मिली है। टेलीग्राम को पूरे देश में बंद करना लगभग वैसा ही है जैसे यदि सड़क पर एक एक्सिडेंट हो, तो सड़कों का उपयोग ही बंद कर दिया जाए अथवा किसी के बालों में जूं पड़ जाए तो पूरा सिर ही काट दिया जाए।

यदि प्रधानमंत्री कार्यालय एक परीक्षा की निगरानी जैसे रूटीन के काम में लग जाए तो देश का संचालन कम करेगा? जो काम बिचल्लू साधारण प्रकृति का है उसे इतना बड़ा-चढ़ा कर बत दिया गया है जैसे परीक्षा कराना संभव सा कार्य हो गया है। हमारे पड़ोसी देश चीन में लगभग 1-2 करोड़

विद्यार्थी प्रतिवर्ष परीक्षा में बैठते हैं और वह गत 20 सालों में कोई पेपर भी लोक नहीं हुआ। कारण स्पष्ट है, यहाँ डर इतना है कि एक बार इस प्रकार की घटना होने पर संबंधित व्यक्तियों को फांसी तक हो सकती है।

नीट की परीक्षा दुबारा कराने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उन्हें मीडिया में तो बहुत स्थान मिल सकता है, किंतु यह नीट की परीक्षा कराने का कोई सही तरीका नहीं कहा जा सकता। यह परिपाटी उचित भी नहीं है। जिसका जो काम है, वह उसे सही तरह करे, यह आवश्यक है। एन टी ए और शिक्षा मंत्रालय का काम यदि प्रधानमंत्री कार्यालय करेगा तो फिर शिक्षा मंत्रालय को अवसर उपलब्ध कराने पर सरकार

नीट के पेपर आउट होने पर कई विद्यार्थियों ने आत्महत्या की है और अनेक छात्र मानसिक अवसाद में चले गए हैं। उसे देखते हुए, पूरी शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था पर ही पुनर्विचार हो आवश्यकता है। क्यों किसी विद्यार्थी के भविष्य का निर्धारण केवल 3 घंटे की परीक्षा से कर दिया जाता है? क्या उन्हें विभिन्न प्रकार के अन्य वैकल्पिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर सरकार विचार नहीं कर सकती ताकि वह जीवन के अमूल्य तीन-चार वर्ष केवल एक परीक्षा पर न लगा दें, और उसमें असफल होने पर अपने जीवन का अंत ही कर लें? जीवन अमूल्य है और इसकी रक्षा करना सर्वोपरि प्राथमिकता है, परिवार के लिए भी और सरकार के लिए भी।

आशा है सरकार परीक्षाओं के आयोजन के साथ ही शिक्षा और रोजगार की पूरी व्यवस्था पर गंभीरता से पुरानवलोकन करेगी और आवश्यक कदम उठाएगी ताकि किस प्रकार की स्थिति नीट परीक्षा के पेपर आउट होने से हुई है वैसी स्थिति देश में उत्पन्न न हो और युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ होने से बचा सके।

-अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

ग्रामीण सेवा शिविर बना जनकल्याण का केंद्र

पावटा, (निर्स)। पावटा तहसील के ग्राम प्रेमनगर एवं ब्लाक विराटनगर की ग्राम पंचायत छोटोली में शुक्रवार को आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। शिविर का आयोजन विधायक कुलदीप धनकड़ के मुख्य आतिथ्य एवं विराटनगर उपखंड अधिकारी कपिल कुमार व पावटा उपखंड अधिकारी डॉ. साधना शर्मा के निदेशन में हुआ। शिविर में विभिन्न विभागों के

अधिकारियों ने आमजन को समस्याओं का मौके पर समाधान किया तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। शिविर के दौरान ग्राम पंचायत छोटोली में कई प्रकरणों का निस्तारण किया गया। वहीं शिविर में सफलता की कहानी लिखते हुए ग्राम जादू का बास निवासी कोयली देवी पत्नी महेश गुर्जर को ग्रामीण सेवा शिविर में मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना के तहत निःशुल्क बीमा पॉलिसी प्रदान की गई। कोयली देवी ने

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना से कोयली देवी व बर्फी देवी को मिली राहत

बताया कि पहले पशुओं का बीमा कराने के लिए भारी प्रीमियम राशि जमा करवानी पड़ती थी, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ जाता था। लेकिन अब राज्य सरकार की इस योजना से उन्हें बिना किसी शुल्क के बीमा

सुविधा मिली है। उन्होंने सरकार एवं पशुपालन विभाग का आभार जताते हुए अन्य पशुपालकों से भी योजना का लाभ लेने की अपील की।

वहीं पावटा तहसील के ग्राम प्रेमनगर निवासी बर्फी देवी की कहानी भी सरकारी योजनाओं की सफलता को दर्शाती है। बर्फी देवी के लिए पशुपालन आजीविका का प्रमुख साधन है, लेकिन पहले पशुओं के बीमार होने और उपचार पर होने वाले खर्च से उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का

सामना करना पड़ता था। मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना के अंतर्गत पशुओं का बीमा होने से उन्हें आर्थिक सुरक्षा का भरोसा मिला। इन शिविरों में पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कोयली देवी और बर्फी देवी जैसी सफलता की कहानियाँ इस बात का प्रमाण हैं कि सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलने पर ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।

शिविर में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक करेगा।

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक करेगा।

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बने लगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों योजना का क्रियान्वयन होगा।

मानसिक तनाव दूर होगा। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बने लगे। व्यावसायिक यात्रा संभव है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। धन हानि का भय है। आजकल घर-परिवार में अनावश्यक धन खर्च होगा। आज समय अनर्गल करने में खराब हो सकता है।

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बने लगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। नवीन कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आज आवश्यक कार्यों में विलंब हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

परिवार में उत्सव समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में बुध-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटके हुए कार्य बने लगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



पंडित अनिल शर्मा

राशिफल

शनिवार 20 जून, 2026

द्वितीय ज्येष्ठ मास (शुद्ध), शुक्ल पक्ष, षष्ठि तिथि, शनिवार, विक्रम संवत् 2083, मघा नक्षत्र प्रातः 9:26 तक, वज्र योग दिन 12:48 तक, तैत्तििल करण दिन 3:47 तक, चन्द्रमा आज सिंह राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मिथुन, चन्द्रमा-सिंह, मंगल-मेघ, बुध-मिथुन, गुरू-कर्क, शुक्र-कर्क, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह
आज रविवार दिन 9:26 तक है। आज अरण्य षष्ठि व्रत, विन्ध्यवासिनी पूजा है।
श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ 7:20 से 9:03 तक, चर 12:28 से 2:11 तक, लाभ अमृत 2:11 से 5:36 तक।
राहुकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 5:37, सूर्यास्त 7:19

मेघ
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी।

तुला
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बने लगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे।

वृष
घर-परिवार में अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्यों सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी और व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक सफलता से मनोबल बढ़ेगा। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।